

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2479

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि

2479. श्री अरुण नेहरू:

कु. सुधा आर.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान वैश्विक बाजार के रुझान, आयात लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव सहित घरेलू सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु और अन्य राज्यों में जहां सोने का पारंपरिक उपयोग अधिक है, त्योहारों और शादियों के मौसम में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल के कारण परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव का संज्ञान लिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मूल्यवान धातुओं की कीमतों को स्थिर करने और उनमें अस्थिरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतियां बनाई गई हैं और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का सांस्कृतिक और धार्मिक अवसरों के दौरान परिवारों के लिए सोने और चांदी को अधिक किफायती बनाने के लिए आयात शुल्क में कमी, करों को युक्तिसंगत बनाने, सब्सिडी या कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत जैसे राहत उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2014 से अब तक आयातित सोने और चांदी की वर्ष-वार मात्रा और मूल्य कितना है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास उपलब्ध सोने के भंडार से रुपये (आईएनआर) के मूल्य को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का खुदरा बाजार में बेचे जा रहे सोने और चांदी की कीमतों के मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें विनियमित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) सोने और चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं की घरेलू कीमतें मुख्य रूप से उनकी वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कीमतों (अमेरिकी डॉलर में), भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर और लागू करों/शुल्कों द्वारा निर्धारित होती हैं। कीमतों में हालिया उछाल का मुख्य कारण बढ़ा हुआ भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक विकास को लेकर अनिश्चितता है, जिसने सुरक्षित मांग को बल देने के साथ दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और प्रमुख संस्थानों द्वारा सोने की भारी मात्रा में खरीद शामिल है।

(ख) हालांकि वर्तमान वर्ष में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि का रुझान देखा गया है, इन मूल्यवान धातुओं पर सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक निर्भरता के अनुसार राज्यों या जनसंख्या समूहों में इसके अलग-अलग प्रभाव हो सकते हैं। उनका योगदान दोहरा होता है—ये न केवल उपयोग की वस्तु हैं, बल्कि निवेश का एक साधन भी हैं, क्योंकि इन्हें अनिश्चितताओं से बचाव के लिए सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। इस प्रकार, सोने या चांदी की कीमत में वृद्धि निश्चित रूप से परिवारों की संपन्नता को प्रभावित करता है, क्योंकि मौजूदा सोने या चांदी के भंडार का अनुमानित मूल्य बढ़ जाता है। भावी खरीदारों के लिए, खरीदारी एक प्रकार की संपत्ति (नकदी) से दूसरी (सोना या चांदी) में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है।

(ग), (घ) और (छ): जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, मूल्यवान धातुओं की कीमतें बाजार द्वारा तय होती हैं और मूल्य निर्धारण में सरकार शामिल नहीं होती है। फिर भी, उपभोक्ताओं को राहत देने के उपाय के तौर पर, सरकार ने जुलाई 2024 में सोने के आयात पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया। सरकार ने भौतिक सोने की मांग को कम करने और अप्रयुक्त घरेलू सोने को जुटाने के लिए स्वर्ण मुद्राकरण योजना (जीएमएस), स्वर्ण विनिमय-व्यापार निधि (ईटीएफ) और संप्रभु स्वर्ण बांड योजना जैसे उपाय शुरू किए, ताकि मांग का कुछ भाग नए आयात के बजाय स्थानीय भंडार से पूरा हो सके और जिससे बाह्य जोखिम और मूल्य दबाव कम हो सकें। आरबीआई और सरकार द्वारा नामित एजेंसियों, बैंकों और रिफाइनरियों के माध्यम से बुलियन आयात को नियंत्रित करने से ट्रसेबिलिटी में सुधार, अवैध बाजार (ग्रे-मार्केट) चैनलों को कम करता है और घरेलू कीमतों को कमी या सट्टेबाजी के कारण होने वाली तेजी के बजाय वैश्विक मानकों का अधिक सुचारू रूप से अनुसरण करने में मदद करता है।

(ड): वर्ष 2014 से सोने और चांदी के आयात (मात्रा और मूल्य) का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है;

वर्ष	सोना		चाँदी	
	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2014-15	9,15,471	34,407.18	77,07,855	4,523.51
2015-16	9,68,063	31,770.74	74,28,856	3,742.74
2016-17	7,80,152	27,518.03	33,62,551	1,839.17
2017-18	9,55,333	33,657.21	58,79,280	3,213.80
2018-19	9,82,711	32,910.06	74,74,205	3,748.22
2019-20	7,19,935	28,229.67	54,21,724	2,727.82
2020-21	6,51,235	34,603.94	14,86,001	790.36
2021-22	8,79,046	46,165.58	44,21,680	32,76.18
2022-23	6,78,346	35,016.29	81,56,795	5,294.58
2023-24	7,48,288	42,561.70	60,58,434	4,457.97
2024-25	7,57,093	58,006.37	51,64,372	4,827.25
2025-26 (सितम्बर तक)	2,99,768	26,514.46	28,20,728	3,219.17

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

(च): भारतीय मुद्रा आरबीआइ अधिनियम, 1934 की धारा 33 के अनुसार आरबीआइ द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों का समर्थन प्राप्त है, जिसके लिए आरबीआइ को सोने के सिक्कों, सोने के बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियों, रुपये के सिक्कों और रुपये की प्रतिभूतियों को इस तरह की कुल राशि के लिए रखने की आवश्यकता होती है जो जारी की गई कुल मुद्रा से कम नहीं है। 31 मार्च 2025 तक, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 879.58 मीट्रिक टन सोना था जो 31 मार्च 2024 को 822.10 मीट्रिक टन की तुलना में सोना था, 57.48 मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। ये सोने की होल्डिंग्स भारतीय रुपये में विश्वास को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था की समग्र बाहरी स्थिरता में सहायक हैं।
